

भ्रष्टाचार की शिकायतों को 'ढंडे बस्ते' में डालने का नतीजा अब महापुरुषों के सम्मान से भी खिलवाड़

आने वाले समय में 'संभाग पोस्ट' करेगा बड़े स्तर पर खुलासा



पिछले कई सालों से संभाग पोस्ट लगातार इन भ्रष्टाचारों को उजागर करते आ रहा है...

एआई जनरेटड फोटो



छाया जोशी



जितेंद्र मेड़ा



मनीष महाजन

मनीष महाजन और जितेंद्र मेड़ा का निलंबन तो सिर्फ ट्रेलर, पूरी फिल्म तो शिकायतों की फाइलों में दफन, प्रशासनिक अनदेखी ने बढ़ाए हौसले, भ्रष्टाचार केवल लापरवाही तक सीमित नहीं कमीशनखोरी का दीमक 'मुखिया' स्तर से शुरू होकर नीचे तक फैला हुआ है।

(विस्तृत समाचार पृष्ठ 3 पर)

सुविचार

अहंकार और संस्कार में फर्क है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है. !!

संपादकीय

बजट 2026 में इन क्षेत्रों पर सरकार का फोकस

आज दुनिया जिस जियो-पॉलिटिकल उथल पुथल से गुजर रही है और उसकी वजह से देश के सामने जो मुश्किलें हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उनसे बाहर निकलने का एक रोडमैप पेश किया। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफी जोर दिया गया है। सरकार ने उ3इ में इसका योगदान 25% तक करने का लक्ष्य रखा है, जबकि अभी तक 20% का लक्ष्य भी हासिल नहीं किया जा सका है।

घरेलू इकॉनमी पर फोकस

इसे देखते हुए वित्त मंत्री ने 6 प्रायॉरिटी क्षेत्रों पर ध्यान दिया। इनमें सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, टेक्सटाइल, एर्श और अर्बन इकॉनमिक क्लस्टर शामिल हैं। सरकार का फोकस डोमेस्टिक इकॉनमी को और मजबूत करने पर है, ताकि देश को बाहरी झटकों से बचाया जा सके। डेयरी, फिशरीज और एग्रीकल्चर एंफ्लॉयमेंट को मजबूती देने के लिए भी सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनका पॉजिटिव असर आने वाले वक्त में दिख सकता है। इसके साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का ध्यान बना हुआ है। वित्त वर्ष 2027 में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10% की बढ़ोतरी के साथ 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया गया है। पिछले कई वर्षों से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तेजी की सरकार की उम्मीद पूरी नहीं हुई है। ऐसे में मजबूत ग्रोथ के लिए वह इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर निवेश बढ़ाना जारी रखेगी।

क्रिटिकल सेक्टर

इसके साथ स्ट्रैटिजिक पहलू को ध्यान में रखकर क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ जैसे सेमेंट को बढ़ावा देने की बात भी सरकार ने कही है। कुछ समय पहले जिस तरह से चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी थी, उसे देखते हुए यह पहल अहम है। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा और क्लाउड सर्विसेज जैसे क्षेत्रों को लेकर भी ऐलान किए गए हैं, जो तेजी से बदलती दुनिया और जियो-पॉलिटिक्स के लिहाज से अहमियत रखते हैं।

अगला लक्ष्य

बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने के लक्ष्य की ओर देख रहा है। वित्त वर्ष 2026 में वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत की 7.4% की अनुमानित GDP ग्रोथ बड़ी बात कही जा सकती है। वित्त वर्ष 2027 में सरकार ने ग्रोथ के 7% रहने का अनुमान लगाया है, जो दुनिया के बड़े देशों में सबसे अधिक होगी।

वित्तीय अनुशासन

इस बजट में ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने के साथ सरकार ने फिस्कल डेफिसिट पर नियंत्रण को लेकर भी पॉजिटिव घोषणाएं की हैं। वित्त वर्ष 2026 में डेफिसिट जहां उ3इ का 4.4% रहा, वहीं अगले वित्त वर्ष में इसके लिए 4.3% का लक्ष्य रखा गया है। भारत की सॉवरेन रेटिंग के लिहाज से यह आंकड़ा अहम है। रेटिंग मजबूत रहने से घरेलू कंपनियों-संस्थानों की कर्ज जुटाने की लागत कम रहती है।

कंजम्पशन ग्रोथ अहम

भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद कंजम्पशन है। देश की उ3इ में इसका योगदान 60% के करीब है। पिछले साल के बजट में इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर इनकम टैक्स माफ कर दिया था। पिछले फेस्टिव सीजन से पहले सरकार ने उऊ दरों को तर्कसंगत बनाया था। साथ ही, रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में कटौती के हालिया साइकल में 0.75 बेसिस पॉइंट की कमी की है। इससे भी कंजम्पशन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बजट में सरकार के वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की घोषणा के बाद रिजर्व बैंक क्या कदम उठाता है, इस पर एक्सपर्ट्स की नजरें रहेंगी।

डील का इंतजार

छोटे निवेशकों को बायबैक पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने की घोषणा कर जरूर एक राहत दी गई है, लेकिन इंडिविजुअल प्रमोटर और एंटीटी प्रमोटर के लिए इसकी दरें अलग रखी गई हैं। सवाल है कि कहीं इससे प्रमोटरों की दिलचस्पी बायबैक योजनाएं लाने में कम तो नहीं होगी? मार्केट लंबे समय से अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पक्के संकेत नहीं मिले हैं।

केंद्रीय बजट 2026: भारत के फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिक क्षेत्र के लिए नई सुबह

स्वास्थ्य और सुलभता की दिशा में ऐतिहासिक छलांग लगाता केंद्रीय बजट 2026 ने भारत के फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र को नई दिशा दे दी है। सरकार ने इस बजट के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब केवल जेनेरिक दवाओं का निर्माता नहीं, बल्कि वैश्विक बायोलॉजिक और नवाचारी औषधियों का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया विज़न को आगे बढ़ाते हुए, इस बजट में फार्मा व बायोटेक क्षेत्र के लिए लगभग रु. 9,000 करोड़ का समर्पित प्रावधान किया गया है।

इसमें से रु. 3,000 करोड़ बायोलॉजिक एवं बायोसिमिलर अनुसंधान के लिए, रु. 2,500 करोड़ API व फर्मेंटेशन आधारित दवाओं के स्वदेशी उत्पादन हेतु PLI योजना के विस्तार के लिए, और रु. 1,500 करोड़ बायोफार्मा पार्क व इनक्यूबेशन सेंटरों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, रु. 1,000 करोड़ नियामक ढांचे को सशक्त बनाने के लिए रखे गए हैं, जिससे डिजिटल अनुमोदन प्रणाली, तेज़ क्लिनिकल ट्रायल प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नियमन संभव हो सकेगा। यह कदम उद्योग में निवेशकों का विश्वास और रोगियों की सुरक्षा—दोनों को मजबूत

करेगा। इस बजट का सीधा लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, जहाँ इंदौर पहले से ही एक सशक्त फार्मा और शिक्षा केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मेडिकल कॉलेज और शोध संस्थान अब राष्ट्रीय बायोलॉजिक मिशन का हिस्सा बनेंगे। इससे इंदौर को बायोलॉजिक स्टार्टअप्स, रिसर्च लैब्स और निर्यात आधारित उत्पादन का केंद्र बनाने की राह खुलेगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बायोलॉजिक और उन्नत थैरेपी आम नागरिकों तक पहुँच सके। सार्वजनिक अस्पतालों के लिए बायोसिमिलर दवाओं की खरीद, आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवरेज



डॉ. महावीर छाजेड प्राचार्य - ऑक्सफोर्ड इंटरनैशनल कॉलेज (फार्मेसी), इंदौर।

और मूल्य नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाएगा। भारत का फार्मा भविष्य उज्ज्वल है और वह भविष्य अब साकार होने जा रहा है।

बजट 2026 विशेष लेख

भारत के बजट 2026 में उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित एसएमई निधि की व्यवस्था: उद्यमों के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका

भारत, जो अपनी विविधताओं और जटिलताओं के लिए जाना जाता है, ने हमेशा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं। 2026 के बजट में 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित एसएमई निधि की व्यवस्था एक ऐसा कदम है जो उद्यमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और इस निधि का उद्देश्य इन उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करके भारतीय उद्योग के विकास को गति देना है। उद्यमों की सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए यह निधि न केवल आर्थिक विकास में सहायक होगी, बल्कि यह रोजगार के नए अवसरों को भी जन्म देगी। युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए, यह बजट गरीब, शोषित और वंचित समुदायों के उद्धार के लिए प्रतिबद्धता दर्शाता है। जब युवा वर्ग नौकरी के बजाय उद्यमिता की ओर आकर्षित होगा, तब यह न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद होगा।

सरकार ने सार्वजनिक पूंजीगत

व्यय को वित्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। यह न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार करेगा, बल्कि विभिन्न उद्योगों में निवेश की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा। ऐसे में, एसएमई निधि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहित करने में किया जा सकता है। इससे उद्यमिता की भावना को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी सशक्त किया जा सकेगा।

इसी तरह, पर्यावरण की दृष्टि से सतत यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच सात उच्च गति रेल गलियारे 'वृद्धि परिवहन संपर्क' के रूप में विकसित किए जाएंगे। यह परिवहन प्रणाली न केवल लोगों की आवागमन की सुगमता को बढ़ाएगी, बल्कि व्यवसायों में कच्चे माल की लागत को भी कम करेगी। इससे एसएमई को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वे अब अपनी सेवाओं और उत्पादों को सस्ती दरों पर विभिन्न बाजारों में पहुंचा सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत के बजट

में महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं। भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई 15,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा 500 कॉलेजों में एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉम्पिक्स) कंटेंट निर्माण लैब की स्थापना करेगा। इस पहल से विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रावधान तथा नवाचार की दिशा में एक नया अवसर मिलेगा। इसके अलावा, उच्च शिक्षा और एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) संस्थानों में छात्राओं की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण करने की योजना प्रस्तुत की है। यह न केवल लिंग समानता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, बल्कि इससे समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप उद्यमिता में भी वृद्धि होगी। खेलों के क्षेत्र में भी सरकार की पहलें सराहनीय हैं। 'खेलो इंडिया मिशन' अगले दशक में खेल क्षेत्र को बदल देगा, जिससे युवा पीढ़ी को न केवल शारीरिक विकास होगा बल्कि वे



प्रो. (डॉ.) पुनीत कुमार द्विवेदी (अर्थशास्त्री), समूह निदेशक, ऑक्सफोर्ड-इंदौर इंटरनैशनल शिक्षा समूह इंदौर

मानसिक रूप से भी कहीं अधिक सशक्त बनेंगे। इन सभी पहलों के माध्यम से, भारत का बजट 2026 न केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित है, बल्कि यह सामाजिक समावेशिता और स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। समर्पित एसएमई निधि, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ, यह बजट भारत के उद्यमों के विकास को एक नई दिशा देने में सक्षम होगा। युवाओं के हाथों में भविष्य है, और सरकार की यह स्थायी दृष्टिकोण उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी। यह एक प्रेरणादायक समय है जहाँ उद्यमिता केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि अवसरों का महासागर बन गया है।

बजट 2026: विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला 'प्रगतिशील बजट'

1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वर्णिम युग की आधारशिला है। यह बजट 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' का बेहतरीन समन्वय है। देश के 99% औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपये के 'ग्रोथ फंड' का प्रावधान एक क्रांतिकारी कदम है। इससे 2000 इंडस्ट्री क्लस्टर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर सृजित होंगे। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और टेक्सटाइल पार्क जैसे निवेश भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी में भारत की धाक जमाएंगे। आयकर कानूनों में सरलीकरण का स्वागत योग्य है, मिसरिपोर्टिंग पर पेनल्टी को 200% से घटाकर 100% करना और छुई दायित्व करने की तिथियों का तार्किक निर्धारण (31 जुलाई और 31 अगस्त) करदाताओं और प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत देगा। छुई संपत्तियों की खरीद पर पैन-आधारित टीडीएस प्रक्रिया और पोर्टफोलियो निवेश की सीमा 5% से बढ़ाकर 10% करना विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि रेल कॉरिडोर, केमिकल पार्क और आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों के माध्यम से भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र बनाने का रोडमैप है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया आयकर कानून कर प्रशासन की जटिलताओं को समाप्त कर एक पारदर्शी भारत की नींव रखेगा।

- सचिन बंसल, उद्योगपति एवं कोषाध्यक्ष भाजपा महानगर

भ्रष्टाचार की शिकायतों को 'ठंडे बस्ते' में डालने का नतीजा

अब महापुरुषों के

सम्मान से भी खिलवाड़

SPECIAL REPORT

नवीन गलकर



एआई जनरेटेड फोटो

खरगोन। नगर पालिका परिषद खरगोन में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब जिम्मेदार अधिकारियों को न तो नियम-कायदों का डर रहा है और न ही जनता की आस्था का। जननायक टंट्या मामा की मूर्ति स्थापना मामले में हुई लापरवाही और अनियमितता के बाद मनीष महाजन और जितेंद्र मेड़ा का निलंबन इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि जब शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होती, तो अधिकारियों के हौसले किस कदर बढ़ जाते हैं।

नगर पालिका के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई एक शिकायत नहीं है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी, कागजी घोड़े दौड़ाने और बजट की बंदरबांट की दर्जनों शिकायतें की गईं। लेकिन विडंबना देखिए, शिकायतों का 'कब्रिस्तान' बनी नगर पालिका ने अधिकांश

शिकायतों को या तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया या जांच के नाम पर 'ठंडे बस्ते' में डाल दिया, इंदौर से भोपाल तक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का विवेक देखिए, जिनके कार्य में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत हुई उन्हीं को जाँच की कमान सौंप दी गई, इस कृत्य को क्या समझा जाए। शिकायतों में इन भ्रष्टाचारियों को ही जांच करने का जिम्मा सौंप दिया जाएगा, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? पूर्व में हुई कई जांचें महज खानापूती बनकर रह गईं। 'संभाग पोस्ट' ने समय-समय पर नगर पालिका के काले कारनामों को उजागर किया था। खबरों के माध्यम से प्रशासन को सचेत किया गया था कि यदि इन 'दीमकों' पर लगाम नहीं कसी गई, तो शहर की व्यवस्था खोखली हो जाएगी। लेकिन शासन-प्रशासन की चुप्पी ने यानि मौन समर्थन ने इन अधिकारियों को अभयदान देने का काम किया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। मामला

टंट्या मामा की मूर्ति स्थापना में हुई गंभीर लापरवाही का है। इस संवेदनशील मुद्दे पर जिस तरह की कार्यप्रणाली अपनाई गई, उसने समाज के हर वर्ग को आक्रोशित कर दिया है। मनीष महाजन और जितेंद्र मेड़ा पर गिरी गाज ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नगर पालिका के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। वर्तमान में शहर के बाजारों और गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा टंट्या मामा मूर्ति मामले में हुए 'यू-टर्न' की है। जयस संगठन द्वारा ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर किया गया धरना अचानक शांत हो गया। आंदोलन का इस तरह एकाएक रुक जाना मामले को और अधिक संदिग्ध बना रहा है। आधिकारिक कारण भले ही सामने न आए हों, लेकिन नगर में यह चर्चा तेज है कि यह फैसला नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी के इशारे पर हुआ है। स्थानीय स्तर पर यह आरोप लग रहे हैं

कि पूरे प्रकरण में अध्यक्ष के पुत्र दक्ष जोशी का नाम सामने आने के बाद, उन्हें बचाने की कवायद शुरू हो गई है। चर्चा है कि रसूख के दम पर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये बातें फिलहाल जनचर्चा का हिस्सा हैं, लेकिन इसने प्रशासन की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगा दिया है और यह सिद्ध कर दिया है कि मुखिया का अधिनस्त अधिकारी और अधिकारी का अधिनस्त कर्मचारी यह लोग जनता की गाढ़ी कमाई से तनख्वाह तो पूरी लेते हैं मगर जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाते, जिस प्रकार कर्मचारी के अच्छे कार्य का श्रेय पुरी अधिकारीक लॉबी लेती हैं उसी प्रकार से दोषी होने पर दोष की सजा में उन अधिकारियों का हिस्सा क्यों नहीं होता जबकि भ्रष्टाचार में बगैर अधिकारियों के सहयोग के भ्रष्टाचार होना

संभव नहीं हैं। ऐसे लोग जनता के नमक से नमक हलाली की जगह नमक हरामी जरूर करते हैं। 'संभाग पोस्ट' पहले भी नगर पालिका में चल रहे 143 कमीशन के खेल का पर्दाफाश कर चुका है। और आने वाले समय में संभाग पोस्ट बड़े स्तर पर खुलासा करेगा जिसमें कई बड़े नामों का पर्दाफाश होगा यह कमीशनखोरी का दीमक 'मुखिया' स्तर से शुरू होकर नीचे तक फैला हुआ है। नगर पालिका खरगोन में भ्रष्टाचार अब केवल आर्थिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक पंगुता का प्रतीक बन चुका है। संभाग पोस्ट एक बार फिर प्रशासन को आगाह कर रहा है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो भ्रष्टाचार का यह 'असुर' खरगोन के विकास और उसकी व्यवस्थाओं को पूरी तरह निगल जाएगा। नगर की शुचिता और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन

को चाहिए कि वह विगत वर्षों में भ्रष्टाचार के जितने भी मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं, उन फाइलों को दोबारा खोले और दोषियों की जवाबदेही तय करे। अक्सर देखा गया है कि जांच टीमों में नगर पालिका के ही अधिकारियों को शामिल किया जाता है। जांच दल में बाहरी और निष्पक्ष अधिकारियों को नियुक्त किया जाए ताकि संलिप्तता की गुंजाइश न रहे। पिछले दो-तीन वर्षों के भीतर शहर में जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं, उनका तकनीकी और वित्तीय ऑडिट अनिवार्य रूप से कराया जाए, साथ ही गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही हो। यदि अब भी ध्यान नहीं दिया गया, तो खरगोन की जनता का सरकारी तंत्र से विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा और शायद जनता को ही खुद सड़क पर उतरकर दोषियों को सजा देनी होगी।

अब निगम बनाएगा कम्युनिटी हॉल और नए सरकारी स्कूल भवन

झोन 10 के परिसर में भी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त कक्षों का होगा निर्माण

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

नगर निगम अब शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीनों पर कम्युनिटी हॉल बनाने से लेकर पुराने सरकारी स्कूलों को तोड़कर नए भवन बनाने की तैयारी की है। इसके लिए आज टेंडर भी जारी किए हैं। नगर निगम शाला प्रकोष्ठ द्वारा शहर के कई जर्जर और खतरनाक स्कूल भवनों को तोड़कर उन्हें नया बनाने का काम किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह कार्रवाई विभिन्न कारणों के चलते ठप पड़ी थी। अब निगम द्वारा फिर से कार्य शुरू कर दिए गए हैं, ताकि सरकारी स्कूल को तोड़कर पूरी तरह नया बनाया जा सके। इसी तरह पागनीसपागा के

सरकारी स्कूल से लेकर वार्ड 44 के छोटी खजरानी के शासकीय स्कूल के पुराने भवन को तोड़कर नया बनाने और वार्ड 80 के धन्वंतरि नगर के पुराने जर्जर स्कूल भवन को तोड़कर नया बनाने का टेंडर जारी किया गया है। इन स्कूल भवनों को बनाने पर 30 से 50 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। दूसरी ओर खातीपुरा के शासकीय स्कूल में रिपेरिंग के कार्य के साथ-साथ बिचौली मर्दाना के सरकारी स्कूल और नया पीठा के उर्दू स्कूल में कई कार्य कराए जाएंगे। निगम अधिकारियों के मुताबिक इसके अलावा झोन 10 के झोनल कार्यालय में कर्मचारियों के लिए नए कक्षों का निर्माण किया जाएगा, ताकि वहां कर्मचारियों के बैठने की पर्याप्त जगह हो सके। कुम्हारखाड़ी में नाग मंदिर के पीछे खाली मंदिर के पीछे कम्युनिटी हॉल बनाने का कार्य भी निगम द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों में सीमेंटीकरण, फुटपाथों को संवारने के भी टेंडर जारी किए गए हैं। टेंडर की प्रक्रिया पूरी करते ही कई जगह काम शुरू कराए जाएंगे।

आपका अपना विश्वसनीय अखबार... हमेशा आपके साथ

संभाग पोस्ट

आप हमसे अपनी समस्याओं को सांझा कर सकते हैं बगैर किसी खौफ के विडियो, फोटो, दस्तावेज के माध्यम से हमारे वाट्सअप नम्बर पर और संभाग पोस्ट के पाठक सदस्य भी बन सकते हैं...

एक वर्ष की सदस्यता लेने पर
अखबार फ्री... तीन विज्ञापन फ्री...
पाठक सदस्यता आईडी कार्ड फ्री...
न्यूज चैनल पर एक एड फ्री...

सम्पर्क 9009919948

1 अप्रैल से बदलेगा आयकर कानून



बजट भाषण की
बड़ी बातें

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसे LRS के नाम से जाना जाता है, के तहत शिक्षा और मेडिकल मकसद से TCS दर को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी करने का प्रस्ताव करती हूँ।
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुपात GDP का 55.6 फीसदी रहने का अनुमान है।
- वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, मैं राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूँ।
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे: मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी।
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2026-27 में, मैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूँ।
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हम 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे।
- मरीजों, खासकर कैंसर से पीड़ित लोगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मैं 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं दवाओं, मेडिसिन और खास मेडिकल मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले खाने के पर्सनल इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी से छूट देने के मकसद से 7 और दुर्लभ बीमारियों को जोड़ने का भी प्रस्ताव करती हूँ।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रक्षा क्षेत्र की यूनिट्स की ओर से मेंटेनेंस, रिपेयर या ओवरऑल ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने के लिए इंपोर्ट किए जाने वाले कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव है।

■ नई दिल्ली । संभाग पोस्ट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए 'विकसित भारत' की नींव को और मजबूत करने का रोडमैप साझा किया है। 'युवा शक्ति' और आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित इस बजट का कुल आकार लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। सरकार ने विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग पर सरकारी खजाना खोल दिया है, वहीं राजकोषीय अनुशासन को भी प्राथमिकता दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (उउड) के 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, जो चालू वित्त वर्ष के 4.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से कम है।

विदेश यात्रा और टैक्स फाइलिंग पर आम आदमी को बड़ी राहत

आम करदाताओं और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने विदेश यात्रा और शिक्षा को किफायती बनाने की दिशा में बड़ा

कदम उठाया है। सरकार ने विदेश यात्रा पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर को 5 से 20 प्रतिशत के स्लैब से घटाकर सीधे 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। यही राहत लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत शिक्षा और चिकित्सा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर भी दी गई है, जहाँ अब टीसीएस की दर 2 प्रतिशत होगी। इसके अलावा, टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को लचीला बनाते हुए 'रिवाइज्ड रिटर्न' दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि व्यापक समीक्षा के बाद तैयार किया गया 'आयकर अधिनियम 2025' आगामी 1 अप्रैल 2026 से प्रभाव में आएगा।

शेयर बाजार के ट्रेडर्स को झटका, F&O और बायबैक पर सख्ती

शेयर बाजार के निवेशकों और विशेषकर ट्रेडर्स के लिए बजट के प्रावधान थोड़े सख्त रहे हैं। सरकार ने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर सिक्वोरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स में बढ़ोतरी की घोषणा की है। फ्यूचर्स पर एसटीटी को 0.02 प्रतिशत से

बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत और ऑप्शंस पर 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, कंपनियों द्वारा शेयरों के बायबैक से होने वाली आय को अब शेयरधारकों के हाथों में 'कैपिटल गेन्स' माना जाएगा और उसी अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि, प्रमोटर्स द्वारा टैक्स आर्बिट्राज को रोकने के लिए उन पर अतिरिक्त बायबैक टैक्स लगाने का भी प्रावधान किया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर सरकार का बड़ा

बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो पिछले बजट के 11.2 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से अधिक है। शहरी विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें मुंबई-पुणे और दिल्ली-वाराणसी जैसे रूट शामिल हैं। इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जोखिम कम करने

के लिए एक 'इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड' स्थापित किया जाएगा और शहरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए 'सिटी इकोनॉमिक रीजन्स' की मैपिंग की जाएगी।

उद्योग और इनोवेशन के लिए 'रिफॉर्म एक्सप्रेस'

औद्योगिक विकास और इनोवेशन के लिए सरकार ने 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' के तहत कई बड़ी घोषणाएं की हैं। भारत को बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए 'बायो-फार्मा शक्ति' योजना और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' का ऐलान किया गया है। एमएसएमई सेक्टर को मदद देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित 'एसएमई ग्रोथ फंड' बनाया जाएगा और डीएच प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी क्रेडिट तक पहुंच आसान की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने के लिए कैंसर के मरीजों के लिए 17 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दी गई है।

भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को मिलेगी तेज स्पीड', पीएम मोदी ने की बजट की तारीफ

केंद्रीय बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विजन को सामने रखते हुए इसे 'अपार अवसरों का बजट' बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करने वाला है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने लगातार बजट पेश कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है।

अपार अवसरों और विकास का बजट

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है, जो विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा। उनके मुताबिक यह बजट सरकार के विजन को जमीन पर उतारने का काम करेगा।

रिफॉर्म एक्सप्रेस को मिलेगी रफ्तार

पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई स्पीड मिलेगी। इससे देश में सुधारों की प्रक्रिया तेज होगी और

आर्थिक ढांचा और मजबूत बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को तेज रफ्तार देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिससे देश में उत्पादन और निवेश बढ़ेगा।

युवाओं को मिलेगा ट्रेड डील का फायदा

पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में भारत ने कई बड़ी ट्रेड डील की हैं। इन समझौतों का सीधा लाभ देश के युवाओं को मिलेगा और उनके लिए नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और यह बजट उस दिशा में मजबूत कदम है।

महंगाई पर नियंत्रण और वैश्विक पहचान

उन्होंने कहा कि इस बजट से महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी। साथ ही यह बजट वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि

इस बजट से रोजगार के नए अवसर बनेंगे और देश में संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हर वर्ग को फायदा पहुंचेगा।

डेटा सेंटर और मेडिकल हब की दिशा में कदम

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत को डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में मेडिकल हब विकसित करने पर भी ध्यान दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास स्किल और स्केल पर है। यह बजट युवाओं के सपनों, उनकी गति और उनके भविष्य का बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक हैं और यह बजट नागरिकों की ताकत को आगे बढ़ाने वाला है।

शहरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और MSME को मजबूती

पीएम मोदी ने कहा कि बजट से शहरों का विकास होगा, आधारभूत संरचना मजबूत होगी और देश में मजबूत व चैंपियन शर्प्स तैयार होंगे, जो अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे।

क्या महंगा-क्या सस्ता

सस्ता

बजट 2026

- 17 कैंसर दवाएं-7 गंभीर बीमारियों की दवाएं
- माइक्रोवेव ओवन
- विदेश घूमना
- ईवी बैटरी, सोलर पैनल
- कपड़े
- जूते

क्या महंगा-क्या सस्ता

महंगा

बजट 2026

- शराब
- कोयला
- स्क्रेप
- लोहा
- फ्यूचर्स एंड ऑप्शन्स

सीएम मोहन यादव ने Budget 2026 को बताया विकसित राष्ट्र का बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार 1 फरवरी 11 बजे संसद में 9वां वित्तीय वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। बजट 2026 में सरकार का वित्तीय वर्ष का रोडमैप आम लोगों के सामने रखा गया। इस बजट के संबोधन के दौरान वित्ती मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने लोगों की यूनिवर्सल सर्विस पर ध्यान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि यही वजह है कि हमें 7 फीसदी का विकास दर हासिल करने में बड़ी कामयागी मिली है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

ऑनलाइन व्यापार का विस्तार

क्या हम फिर आंशिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं?

भारत का इतिहास केवल स्वतंत्रता की गाथा नहीं, बल्कि संघर्ष, बलिदान और चेतना का दस्तावेज़ भी है। हमने सदियों तक गुलामी का दंश झेला—पहले मुगल शासन के अधीन और फिर लगभग दो सौ वर्षों तक अंग्रेज़ों के साम्राज्य में। अंग्रेज़ जब भारत आए तो उन्होंने केवल शासन नहीं किया, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी। व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर छोटे उद्योगों और स्थानीय व्यापार को निगल लिया गया।

विडंबना यह रही कि उस कंपनी को शीर्ष तक पहुँचाने में जिन हाथों ने मेहनत की, वे हाथ अंग्रेज़ों के नहीं, बल्कि भारतीयों के ही थे। किसी भी संस्था को मजबूत बनाने में जितना योगदान मालिक

का होता है, उससे कम योगदान उसके कर्मचारियों का नहीं होता। अंग्रेज़ी हुकूमत की सेना में भी अधिकांश सिपाही भारतीय ही थे, जो अपने ही देशवासियों के खिलाफ युद्ध में खड़े थे—क्योंकि उन्हें 'नमक का कर्ज' चुकाना था।

पर क्या हमने कभी सोचा कि वह नमक, वह वेतन, वह धन—सब इसी देश की मिट्टी से लूटा गया था? अंग्रेज़ हमें हमारा ही धन लौटाकर हमें ही गुलाम बनाए रखे हुए थे।

ऐसे समय में महात्मा गांधी का उदय हुआ। उन्होंने केवल राजनीतिक आज़ादी की नहीं, बल्कि वैचारिक गुलामी से मुक्ति की राह दिखाई। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने देश को एक सूत्र में बाँध दिया। वह समय धन्य

था, जब हम कंधे से कंधा मिलाकर चले, जब विदेशी वस्तुओं की होली जली और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया गया। लेकिन आज प्रश्न उठता है—

वह एकता कहाँ गई?
वह संकल्प कहाँ खो गया?
वह स्वदेशी का भाव क्यों कमजोर पड़ गया?

आज हम इतिहास को एक नए रूप में दोहराते दिखाई दे रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह विदेशी ऑनलाइन कंपनियाँ हैं। ऑनलाइन व्यापार तेज़ी से पांव पसार रहा है और इनमें से अधिकांश कंपनियाँ विदेशी पूंजी से संचालित हैं। सस्ते और ब्रांडेड सामान के आकर्षण में हम अपने ही देश के स्थानीय व्यापारियों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं।



यह एक प्रकार का अदृश्य शीत युद्ध है—जो दिखाई नहीं देता, पर धीरे-धीरे देश की आर्थिक शक्ति को कमजोर करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब स्थानीय बाजारों को खत्म कर देंगे, तब विकल्प भी वही तय करेंगे और कीमतें भी। तब न ग्राहक स्वतंत्र रहेगा, न व्यापारी।

इस संकट से निपटने के लिए दोनों पक्षों को समझौता करना होगा। स्थानीय व्यापारियों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और उचित मूल्य अपनाने होंगे, वहीं ग्राहकों

को भी यह समझना होगा कि सस्ता हमेशा हितकारी नहीं होता। देश का पैसा यदि देश में नहीं रुका, तो समाज कमजोर होगा—और कमजोर समाज से मजबूत राष्ट्र नहीं बनता।

आज सरकारें भी 'स्वदेशी अपनाओ' पर ज़ोर दे रही हैं। प्रधानमंत्री स्वयं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान कर चुके हैं। इतिहास गवाह है कि परिस्थितियाँ बार-बार लौटती हैं—बस चेहरे बदल जाते हैं, मुखौटे नए होते हैं।

अब भी समय है। हमें इतिहास से सीख लेनी होगी। विदेशी कंपनियों के अंध समर्थन के बजाय लोकल, स्थानीय और स्वदेशी को प्राथमिकता देनी होगी। नहीं तो वह दिन दूर नहीं, जब वैचारिक गुलामी के साथ-साथ हम एक बार फिर आंशिक गुलामी की जंजीरों में जकड़े होंगे—और इस बार यह गुलामी और भी भयावह होगी, क्योंकि यह हमारी अपनी सुविधा की पसंद से जन्म लेगी।

स्वदेशी केवल नारा नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा है।

संभाग पोस्ट सामाजिक दृढ़ता संकल्प अभियान

अब आपकी आवाज होगी बुलंद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के संग

आज के समाज में हम देख रहे हैं की शहरी परिवेश की बात करें या ग्रामीण परिवेश की आज के परिवेश में व्यक्ति अकेला पड़ता जा रहा है। आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल करते-करते अपने आप को अकेला महसूस करता है, जब उसके ऊपर ऐसी कोई विपत्ति आती है की जब उसके परिवारजन या मित्र बंधु उसका साथ दे। तब वह पता है कि वह अकेला खड़ा है। यह आज के समाज का सत्य है। यह भारत के ७० प्रतिशत लोगों की सच्चाई है वह किसी भी प्रकार की समस्या में हो चाहे पारिवारिक या मानसिक, सामाजिक, प्रशासनिक या चिकित्सकीय हो ऐसी किसी भी समस्या में वह पाता है कि वह अकेला है। और यदि ऐसे मे किसी मोड़ पर कुछ व्यवधान उत्पन्न हो तब वह नीरस हो जाता है, और किसी न किसी प्रकार की गलती कर बैठता है। समाज की ऐसी सबसे बड़ी समस्या को लेकर हमने सामाजिक दृढ़ता संकल्प का अभियान चलाया है जिसके तहत हम उन सभी ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो हमसे जुड़ेंगे तथा वे लोग जो हमसे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, हमारा प्रयास यह होगा कि ऐसी किसी भी समस्या में हम उनके साथ खड़े हो जिस जगह पर वह सही है और उन्हें व्यवधान, समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में संभाग पोस्ट परिवार उनके साथ खड़ा है।

- समाज में एक कहावत प्रचलित है सत्य परेशान हो सकता है। पराजित नहीं हो सकता,
- ईश्वर की इसी प्रेरणा को हमारे मीडिया चैनल हमारे अखबार ने आत्मसात किया है और हम उन सभी समाज जनों के साथ खड़े हैं जिनके साथ सत्य है।
- ईश्वर सत्य का साथ देने वाले उनके अनुयायियों की सहायता करने स्वयं नहीं आते किंतु किसी न किसी माध्यम से सत्य का साथ दे रहे व्यक्ति की सहायता जरूर करते हैं।
- हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमने यह मुहिम चलाई है जिसके तहत यदि आपके साथ सत्य है तो हम आपके साथ सदा खड़े हुए हैं
- हमारे चैनल और हमारे अखबार से जुड़े हुए सभी सदस्य गण जिनकी किसी भी प्रकार की परेशानी अब उनकी नहीं वह हमारी है।
- जब समाज दृढ़ होगा, सत्य की विजय होगी जब एकता और समान व्यवहार और ज्ञान होगा तब हमारा समाज एक नए भारत का दृढ़ निश्चय भारत का निर्माण कर पाएगा
- यदि आपका काम, स्वयं आप और आपका विचार, सत्य के साथ है तो वह आपका नहीं अपितु वह हमारा विचार होगा, क्योंकि आप भारत के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ है
- अब आम आदमी की आवाज आम आदमी की नहीं अपितु उसके साथ हमारी भी आवाज होगी इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे साथ शीघ्र से शीघ्र जुड़े और अपनी आवाज को एक नया आयाम दें और अपने समाज को अपने परिवार को और अपने देश को सशक्त बनाएं
- हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको कोई नया प्रयास नहीं करना केवल सामाजिक दृढ़ता संकल्प संभाग पोस्ट अभियान का एक फॉर्म भरना है

विचार न कीजिए तुरंत संपर्क करें: 9755648321

क्योंकि दृढ़ होगा समाज तो सशक्त होगा भारत और खुशहाल होगा हमारा परिवार
सत्यम्, शिवम्, सुंदरम्। सत्यमेव जयते
भारत माता की जय वंदे मातरम्



आदर्श कॉन्वेंट स्कूल में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पोर्ट्स फिएस्टा 2025 के विजेता सम्मानित



■ इंदौर। संभाग पोस्ट आदर्श कॉन्वेंट स्कूल में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स फिएस्टा 2025 के सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। स्पोर्ट्स फिएस्टा नर्सरी से आठवीं कक्षा तक आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं कराई गईं।

प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, द्वितीय स्थान पर रहने वालों को सिल्वर मेडल तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही पिछले शैक्षणिक वर्ष के क्लास टॉपर्स को भी सम्मानित किया गया, जिन्हें पुरस्कार स्वरूप मोमेंटो भेंट किए गए।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पार्षद हाजी उस्मान पटेल, वरिष्ठ पत्रकार रवि यादव, तथा खजराना क्षेत्र के स्कूल डायरेक्टर्स हाजी अंसार पटेल, तस्लीमुद्दीन शेख और मुनव्वर हुसैन विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का सम्मान स्कूल के डायरेक्टर मोमिन पटेल द्वारा मोमेंटो देकर किया गया।

अतिथियों ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, पढ़ाई पूरी करने, अच्छा इंसान बनने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी। समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावक और विद्यार्थी मौजूद रहे।

कार्यक्रम का सफल संचालन तबस्सुम शेख, मंताशा अंसारी और इरम खान ने किया।

कानून के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से गठित संस्था 'न्यायाश्रय' की राजस्थान टीम का गठन



■ इंदौर। संभाग पोस्ट

कानून के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से गठित संस्था न्यायाश्रय की राजस्थान टीम का विधिवत गठन किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट आकाश यादव को राजस्थान टीम का अध्यक्ष एवं एडवोकेट कुंदन पालीवाल को सचिव के रूप में मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. पंकज वाधवानी, हाई कोर्ट एडवोकेट की गरिमामयी उपस्थिति रही।

उनके साथ उदयपुर के अनेक वरिष्ठ एवं युवा अधिवक्तागण भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राजस्थान टीम के गठन के उपरांत संस्था के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, उदयपुर का दौरा किया गया। इस दौरान न्यायिक प्रक्रिया, अधिवक्ता हितों एवं विधिक जागरूकता से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. पंकज वाधवानी ने इस अवसर पर कहा कि न्यायाश्रय संस्था का उद्देश्य

केवल विधिक सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करना है। राजस्थान टीम का गठन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नव-नियुक्त पदाधिकारियों ने संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने, विधिक जागरूकता फैलाने एवं समाज के कमजोर वर्गों के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।



APPLIED FORENSIC SCIENCE LABORATORY

Email: afslindore23@gmail.com Mobile No: +91 9366381689 +91 9977649317

SERVICES

- Handwriting Examination.
- Signature Examination.
- Fingerprint Examination.
- Deleted Data Recovery from Mobile Phones, Hard Drive.
- Laptop, Desktop Computer, Pen drive.
- Complete Examination of Digital Instrument i.e. Mobile.
- phones, Laptop, Desktop Computers, in case of Hacking.
- Voice Analysis and Voice Comparison.
- Examination of Alteration in any Documents.
- Examination of Erased Writing.
- Examination of Audio Clips and Video Clips.
- Preparation of Fingerprint Records for Corporate Offices.
- Examination of Arson Cases.
- DNA Examination for Paternity and Maternity.
- Forensic Consultancy.
- Forensic Investigation of Insurance Claims.
- Property Investigation.
- Crime Scene Investigation.
- Audio Transcription.

FORENSIC EXPERT

Rakesh Mia
+91 93663 81689

Vijay Panchal
+91 9977649317

Head Office
Applied Forensic Science Laboratory
8/1, 2nd floor, Moti Tabela, Near
Collectorate Office, Indore, MP, 452007

Branch Office
Chandra Forensic Science
lab
Chandigarh/New Delhi

संदीप पवार
Mob :- 98260-68380

KP
|| श्री गणेशाय नमः ||

सीमेंट न्यू नर्मदा ट्रेडर्स

बालू रेती

काली रेती, गिड़ी

ईट एवं बिल्डिंग मटेरियल के विक्रेता

4, मंगलनगर, आई.टी.आई. रोड,
बैंक ऑफ बड़ोदा के पास, पेट्रोल पम्प
के पहले, इन्दौर (म.प्र.)



रामसेवक दुर्वे
9406621084

पूजा

बुक्स एण्ड स्टेशनर्स

6/3, सुंदर अपार्टमेंट, क्लक कालोनी चौराहा, श्री सत्य साई बाल
विनय मंदिर के सामने, इन्दौर मो

- CBCE स्कूल बुक्स
- चिल्ड्रन बुक्स
- ऑफिस स्टेशनरी
- कम्प्यूटर स्टेशनरी
- स्कूल स्टेशनरी एवं
- गिफ्ट आयटम

राहुल जनरल स्टोर्स

शॉप नं. 3 मालवा मिल चौराहा, इंदौर
मो. 9977732802

भारतीय पत्रकार संघ एआईजे द्वारा राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान एवं कल्याण महोत्सव 2026 आयोजित



केसवानी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन, रंजीत सिंह ठाकुर, अमीर शेख, श्याम कुशवाह सहित संगठन के पदाधिकारी एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सम्मान के साथ-साथ उनके कल्याण और अधिकारों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

आयोजन का उद्देश्य पत्रकारों के सामाजिक योगदान को सम्मान देना तथा पत्रकार हितों को सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल करना रहा। कार्यक्रम का समापन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ।

■ खरगोन । संभाग पोस्ट

भारतीय पत्रकार संघ (एआईजे) के तत्वावधान में रविवार, 1 फरवरी को खरगोन स्थित अभ्युदय यूनिवर्सिटी कैम्पस में राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान एवं

कल्याण महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों एवं मध्यप्रदेश के अनेक जिलों से बड़ी संख्या में पत्रकारों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम में खरगोन पुलिस अधीक्षक रविन्द्र वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शकुंतला रुहल, एसडीएम सत्येंद्र कटारे, खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, धुलकोट विधायक केदार डावर,

मनावर विधायक डॉ. हीरालाल अलवे, वरिष्ठ पत्रकार अजीजुद्दीन शेख, भारतीय पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अयोध्या से पधारे संत रामलला सरकार रहे, जिनकी उपस्थिति ने आयोजन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक स्वरूप प्रदान किया। वहीं अनादी टीवी की एंकर पारूल

चेतन टेलर्स

(सूट स्पेशलिस्ट)



सुनिल खटके
मो. 9893118079

30/1. परदेशीपुरा, शिवधाम के सामने, इंदौर

शुद्ध मावे की मिठाइयों के निर्माता एवं विक्रेता

श्री चारभुजा

स्वीट्स एवं नमकीन

गुलाब जामुन, मावाबाटी, काला जामुन, रसगुल्ला इत्यादि

662/9, नेहरु नगर, अटल द्वार, इन्दौर
शाखा: 60, न्यूवेवास रोड, राजकुमार ब्रिज, इन्दौर

डॉ. हिमांशु केलकर

एम.डी., डी.सी.एच.
नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ
मो. 9202238451

क्लिनिक: 20 जी/एच., गीतांजलि अपार्टमेंट, मार्केट रोड, विजय नगर
स्क्रीम नं. 54, इंदौर (म.प्र.) Email : himanshukelkar@rediffmail.com
समय : प्रातः 10.30 से 1.30 बजे, सायं 5.30 से 8.30 बजे तक
निवास : 7-बी, शालीमार टाउनशिप, ए.बी. रोड, इंदौर

॥ श्री गणेश ॥ ॥ जय माँ भगवती ॥

सेवक राम केवट (छोटू उस्ताद)
मो. 9826012658, 9131711406

माँ नर्मदा

केटरर्स

107, नार्थ मुसाखेड़ी, अजयबाग कॉलोनी, इन्दौर
शादी, पार्टी, पिकनिक, जन्मदिन पर कच्ची एवं पक्की रसोई की सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु सम्पर्क करें।

साहित्यकार नर्मदाप्रसाद उपाध्याय व अतुल तारे को मिलेगा वर्ष 2026 का हिन्दी गौरव अलंकरण फ़रवरी में इन्दौर में आयोजित समारोह में होंगे अलंकृत

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

देशभर में हिन्दी के विस्तार के लिए काम करने वाले मातृभाषा उन्नयन संस्थान द्वारा वर्ष 2026 का हिन्दी गौरव अलंकरण सुप्रसिद्ध साहित्यकार नर्मदा प्रसाद उपाध्याय (इन्दौर) और वरिष्ठ पत्रकार अतुल तारे (ग्वालियर) को प्रदान किया जाएगा। हिन्दी गौरव अलंकरण समारोह का यह सातवाँ वर्ष है। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अर्पण जैन 'अविचल' ने बताया कि 'अलंकरण का यह सातवाँ वर्ष है। संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष दो हिन्दी साधकों को 'हिन्दी गौरव अलंकरण' से विभूषित किया जाता है। चयन समिति द्वारा चयनित वर्ष 2026 के लिए इन्दौर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार नर्मदा प्रसाद उपाध्याय व ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार अतुल तारे के हिन्दी के प्रति समग्र अवदान को रेखांकित करते हुए हिन्दी गौरव अलंकरण प्रदान किया जाएगा।

सुप्रसिद्ध साहित्यकार, ललित निबन्धकार व साहित्य एवं कला के अंतर अनुशासन पर कार्य करने वाले, अनेक विधाओं में सिद्धहस्त

लेखक नर्मदा प्रसाद उपाध्याय प्रमुख रूप से कला एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर ललित निबन्ध के लिए पूरे देश एवं विदेश में चर्चित हैं। श्री उपाध्याय ने 18 निबन्ध संग्रह, 30 कला केन्द्रित पुस्तकें लिखी हैं व 20 पुस्तकों का सम्पादन किया है।

सुप्रसिद्ध पत्रकार अतुल तारे वर्तमान में दैनिक अखबार के समूह सम्पादक हैं। आप 40 वर्षों से हिन्दी पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने भी एक दर्जन से अधिक पुस्तकों का लेखन व सम्पादन किया है। अलंकृत होने वाली विभूतियों को संरक्षक राजकुमार कुम्भज, साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे, इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक कर्दम, पूर्व अध्यक्ष अरविंद तिवारी, प्रो. संजय द्विवेदी, मातृभाषा उन्नयन संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितेश गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव भावना शर्मा, राष्ट्रीय सह सचिव सपन जैन काकड़ीवाला, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शिखा जैन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गणतंत्र ओजस्वी, डॉ. नीना जोशी, प्रेम मंगल, मणिमाला शर्मा, अनुपमा समाधिया आदि ने शुभकामनाएँ दीं।



श्री रवि इत्र सुगन्ध भण्डार

गुलाब, मोगरा, चन्दन, परप्युम इत्यादि के थोक एवं खरेदी विक्रेता

प्रोपायटर : रवि सुगन्धी
मो. 9452665448

पता: हीरानगर, मेनरोड, सुखलिया, मिलन गार्डन के पास, इन्दौर

RAVI S. SAHU
Managing Director
+91-98260-77714

रवि

स्वाद का जादू - जोगे घर घर...

मसाले बस चुटकी भर...

मसाले एवं पापड़

RAVI HOME INDUSTRIES

12, Nirmal Nagar, Piplyahana, Indore - 452 001, Ph.: 0731-2490449
Web : www.ravihomeind.com | E-mail : ravisahurhi@gmail.com

अनुप यादव
9617246247

अमन यादव
7773007307
8770131488

आवित्री

हार्डवेयर

सेनेटरी एण्ड पेन्ट्स

92 हीरा नगर MR-10 मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.)

त्रिगुण दास बौरासी

कुलदीप बौरासी
मो. 9405852932

लक्ष्मी

आप्टीशियन

सभी प्रकार के नजर व धूप के चश्मे बनाए जाते हैं

फ़ोन : 0731-2545493

352/2, पाटलीपुरा (भेरू मंदिर के पीछे) प्रिंस टेलर के बीच वाली गली में, इंदौर

क्राइम ब्रांच इंदौर की बड़ी कार्रवाई

31.86 ग्राम एमडी के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, अंतरराष्ट्रीय कीमत 3.20 लाख रुपये



कमल मेघवाल नि.
झालावाड़ राजस्थान

नरेंद्र मेघवाल नि झालावाड़
राजस्थान

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

शहर में अवैध मादक पदार्थों

की तस्करी पर लगाम कसने के उद्देश्य से क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस

द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने 31.86 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी (ए३) के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 लाख 20 हजार रुपये आंकी गई है।

क्राइम ब्रांच इंदौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त एवं तस्करी में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध गोपनीय सूचना संकलन कर प्रभावी

कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान क्राइम ब्रांच टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संदिग्धों की तलाश एवं पतारसी कर रही थी। मालवा रेडीमेड क्लस्टर के सामने, लक्ष्मीबाई नगर मेन रोड पर दो व्यक्ति काले रंग की होंडा दोपहिया वाहन के साथ सड़क किनारे खड़े दिखाई दिए, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुईं। पुलिस को देखकर दोनों घबरा गए, जिस पर टीम ने घेराबंदी कर उन्हें रोका।

पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम

1. कमललाल मेघवाल

निवासी झालावाड़, राजस्थान

2. नरेंद्रलाल मेघवाल निवासी झालावाड़, राजस्थान बताया।

शंका के आधार पर विधिवत तलाशी लेने पर पुलिस ने वाहन की सीट के भीतर छुपाकर रखा गया 31.86 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी बरामद किया। इसके साथ एक दोपहिया वाहन एवं दो वीवो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। कुल जब्त मशरूका की कीमत लगभग 4 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने अवैध लाभ अर्जित करने की मंशा से मादक पदार्थ सस्ते दामों

में खरीदकर इंदौर शहर में नशे के आदी लोगों को महंगे दामों पर बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी कमललाल मेघवाल के विरुद्ध पूर्व में झालावाड़ (राजस्थान) में भी एक अपराध पंजीबद्ध है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 14/2026, धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना अपराध शाखा इंदौर में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मामले में विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

खंडवा रोड पर नशे में धुत लोडिंग वाहन चालक ने चार लोगों को मारी टक्कर, दो की हालत गंभीर

आईटी पार्क के पास तेज रफ्तार वाहन ने कुचला हादसे के बाद लगा जाम, नशे में धुत था चालक

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

मध्यप्रदेश के इंदौर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भंवरकुआ क्षेत्र में आज एक और बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां एक टाटा एस लोडिंग वाहन ने गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में चार लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। पुलिस ने टाटा एस वाहन को जब्त कर लिया है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब के नशे में था। दरअसल, इंदौर



में घायल हुए सभी लोगों को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

घायलों को पहुंचाया अस्पताल

स्थानीय लोगों के मुताबिक लोडिंग वाहन का ड्राइवर शराब के नशे में था। उसने बाइक और अन्य दोपहिया वाहनों को टक्कर मारी। इससे उस पर सवार लोग घायल हो गए और वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गई थी। एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और आरोपी ड्राइवर को पुलिस पकड़कर थाने ले गई।

इलाके में मचा हड़कंप

स्थानीय लोगों का कहना है

कि लोडिंग वाहन का ड्राइवर जिस तरह से गाड़ी दौड़ा रहा था उससे यह साफ समझ आ गया था कि वो नशे की हालत में है। एक के बाद एक वो कई गाड़ियों को टक्कर मारता गया और लोग घायल होकर नीचे गिरते गए। इस दौरान आस-पास मौजूद लोग दौड़े और घायलों को सड़क से उठाकर पुलिस और एंबुलेंस को घटना की सूचना दी।

कहा- फेल हो गए थे ब्रेक

पुलिस ने लोडिंग वाहन के ड्राइवर को हिरासत में लेकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया। इस हादसे में एक युवक के सिर में भी चोट आई है। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। पुलिस वाहन की तकनीकी जांच कराने की बात कह रही है।



इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 32वीं मौत, एक महीने की जंग के बाद अनीता ने तोड़ा दम

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण मरने वालों की संख्या 32 हो गई है। एक महीने से बाम्बे हॉस्पिटल में इलाज करा रही 65 वर्षीय अनीता कुशवाहा की रविवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्हें उल्टी-दस्त की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना में अब तक 3500 से अधिक लोग बीमार पड़ चुके हैं।

28 दिसंबर को हुई तबियत खराब

परिवार वालों के मुताबिक, अनीता पहले बिल्कुल स्वस्थ थीं।

28 दिसंबर को उन्हें उल्टी-दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो दिन बाद छुट्टी मिलने पर उन्हें घर लाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। 1 जनवरी को उन्हें अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से 4 जनवरी को उन्हें बाम्बे हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया।

किडनी फेल होने के बाद कार्डियक अरेस्ट

इलाज के दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। किडनी फेल होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। इस दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी आया। सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी ने उनकी मौत की पुष्टि की है। भागीरथपुरा में अब तक 3500 से ज्यादा लोग इस

बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 450 से अधिक लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। हालांकि, तीन मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से दो आईसीयू में हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

आखिरी चरण में पाइपलाइन सुधार का काम

नगर निगम का कहना है कि इलाके के करीब 30 प्रतिशत हिस्से में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जा रही है। निगम का दावा है कि पानी साफ आ रहा है, लेकिन लोग अभी भी आरओ (RO) और टैंकर के पानी पर ही निर्भर हैं। बाकी 70 प्रतिशत क्षेत्र में पाइपलाइन सुधार का काम आखिरी चरण में है।